बेरोजगारों की संख्या

425. श्री शंकर दयाल सिंह : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में बेरोजगारों की संख्या कितनी है;

(ख) 30 मई, 1991 की स्थिति के अनुसार कितने शिक्षित व अशिक्षित बेरोजगारों के नाम दिल्ली के रोजगार कार्यालय के रजिस्टर में दर्ज थे; और

(ग) गत एक वर्ष के दौरान रोजगार कार्यालयों में पंजीकृत बेरोजगारों में से कितने बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया ?

श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री के० राममूर्ति) (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, मार्च, 1990 में देश में बेरोजगारों (सामान्य प्रमुख स्तर) की संख्या 131 लाख होने का अनुमान लगाया गया है ।

(ख) 30 मई, 1991 की स्थिति के अनुसार, केन्द्र शासित प्रदेश दिल्ली के रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर में शिक्षित (मैट्रिक तथा उससे ऊपर) तथा अशिक्षित (अनपढ़ सहित मैट्रिक से नीचे) रोजगार चाहने वालों की संख्या, यह आवश्यक नहीं कि वे सभी बेरोजगार हों, क्रमश: 6.43 लाख तथा 2.14 लाख है ।

(ग) 1990 के दौरान देश में रोजगार कार्यालयों के माध्यम से 2.64 लाख पंजीकृत रोजगार चाहने वालों को रोजगार प्रदान किया गया ।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि की कीमत में वृद्धि

426. सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा :
डा० जिनेन्द्र कुमार जैन :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 21 मार्च, 1991 के इंडियन एक्सप्रेस में "हाइक इन लैंड प्राइसिज, ओनली आप्शन" नामक शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई भूमि की कीमतों में वृद्धि होती जा रही है ;

(ग) यदि हां, तो दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूमि के विकास के लिये अनुमानत: प्रति एकड़ क्षेत्र-वार कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(घ) क्या किसी अन्य विभागेत्तर संस्था द्वारा खर्च की उक्त धनराशि के औचित्य के बारे में कोई जांच की गयी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस विषय में कोई जांच करायेगी ?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल) : (क) जी, हां ।

(ख) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Housing schemes floated by DDA

427. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) what is the number of housing schemes floated by DDA between 1969 and 1989;

(b) how many of these schemes have been implemented and the applicants have been allotted flats;

(c) what is the backlog in respect of each of the schemes floated during these years;

(d) what are the details of schmes presently undertaken by DDA and by when these schemes are likely to be completed; and